(d) the States where the prices of gram, wheat, rice and other foodgrains have fallen below the minimum procurement prices ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FOOD, AGRICULTURE, COMMUNITY DEVELOPMENT AND COOPERATION (SHRI ANNASAHIB SHINDE) : (a) The main reason for slow progress in the procurement of foodgrains in some of the States is delayed harvesting. The late start of monsoon last year led to late transplantation of paddy and consequently to delayed harvesting. The other reason for slow progress of procurement in some of the States has been the political instability and the consequent reluctance particularly of governments composed of many parties to make an all-out effort. Some damage to crops just before harvest also resulted in procurement not reaching the earlier expectations.

(b) The State Governments concerned are making efforts to intensify procurement but the damage to crops just before harvest in some States will make it difficult to achieve the targets.

(c) A statement showing the quantities of rice and paddy procured in the different States so far and the targets recommended by the Agricultural Prices Commission is laid on the Table of the House. [*Placed in Library See* No. LT-923/68].

(d) No case has been brought to the notice of Government to the effect that the prices of foodgrains of fair average quality have fallen below the procurement prices in any area.

श्रम आन्दोलन

7611. **श्री रघुबीर सिंह शास्त्री** : क्या श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बात का पता लगाने के लिये सरकार ने कोई अध्ययन कराया है कि गत वर्ष श्रमिकों के जो आन्दोलन हुए हैं, उनके पीछे कहां तक राजनैतिक उद्देश्य था; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

श्रम तथा पुनर्वास मन्त्री (श्री हाथी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

फसल बीमा योजना

7612. **श्री रघुबीर सिंह शास्त्री** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सभी राज्य सरकारों ने फसल बीमा योजना के बारे में एक करार किया है;

(ख) यदि हां, तो संशोधित योजना का ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो मतभेद किन बातों पर है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) और (ग). केवल 9 राज्यों में फसल बीमा योजना पर अपने विचार भेजे हैं। अन्य राज्यों से उत्तर प्राप्त नहीं हुए हैं। प्राप्त उत्तरों का एक सारांश सभा के पटल पर रख दिया गया है। [पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या— LT-926/68]

(ख) इस समय योजना में संशोधन करने का प्रश्न ही नहीं होता, क्योंकि अब तक जो उत्तर प्राप्त हुए हैं वे सामान्यतया फसल बीमा योजना का सिद्धान्त रूप से समर्थन ही करते हैं।

आयातित गेहूँ की बिक्री

7613. **श्री रघुबीर सिंह शास्त्री** : क्या खाद्य तथा कृषि मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस वर्ष बाजार में देसी गेहूँ आ जाने के कारण आयातित गेहूँ की बिक्री बहुत कम होती जा रही है;

(ख) सरकार के पास इस समय आयातित गेहूँ का स्टाक कितना है;

(ग) क्या सरकार का विचार आयातित

गेहूँ की कीमत घटाने या उस पर राजसहायता बढ़ाने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो गेहूं की किस प्रकार बिक्री करने का सरकार का विचार है ?

खाद्य, कृषि, समुदायिक विकास तथा सहकार मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे : (क) जी हां। इस प्रकार जितनी आयातित गेहूँ दी जा रही है, उसकी बिक्री में अभी तक कोई कमी नहीं हुई है। तथापि, सरकार इस के देने में कुछ कमी करने की कोशिश कर रही है।

(ख) केन्द्रीय सरकार के डिपो में 1-4-1968 को लगभग 335,000 मीटरी टन गेहूँ उपलब्ध था।

(ग) जी नहीं।

(घ) इस स्टाक के तुरन्त निपटान की कोई जरूरत नहीं है। तथापि, जब कभी आवश्यक होगा तब यह स्टाक सरकार के सामान्य वितरण प्रबन्धों के अधीन दिया जाएगा।

महाराष्ट्र के गांवों में डाकघर

7614. **श्री देवराव पाटिल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में ऐसे गांवों की संख्या कितनी है और उनके नाम क्या-क्या हैं जहां ग्राम पंचायतें तो हैं परन्तु डाकघर नहीं हैं;

(ख) क्या ऐसे सभी गांवों में डाकघर खोलने का विचार है; और

(ग) यदि हां, तो महाराष्ट्र के यवतमाल जिले में ऐसे कौन-कौन से गांव हैं जहां डाकघर नहीं खोले गये हैं यद्यपि वहां पर ग्राम पंचायतें हैं तथा वहां पर कब तक डाकघर खोलने का विचार है ?

संसद कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मंत्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और इसे यथा-समय सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

महाराष्ट्र में तारघर

7615. **श्री देवराव पाटिल** : क्या संचार मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1966-67 और 1967-68 में महाराष्ट्र में जिलावार कितने तारघर खोले गये, तथा वे कहां-कहां पर खोले गये हैं;

(ख) 1968 और 1969 में कहां-कहां पर तार घर खोलने का विचार है; और

(ग) क्या महाराष्ट्र में ऐसे सभी स्थानों पर तार घर खोले गये हैं जहां पंचायत समिति मुख्यालय स्थित है और यदि नहीं, तो वहां पर कब तक तारघर खोले जायेंगे ?

संसद कार्य विभाग तथा संचार विभाग में राज्य मन्त्री (श्री इ० कु० गुजराल) : (क) से (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और इसे शीघ्र ही सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

आटा मिलों को देसी गेहूँ का सप्लाई किया जाना

7616. **श्री देवराव पाटिल** : क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आटा, सूजी और मैदा का उत्पादन करने के लिये आटा मिलों को आयातित गेहूँ का मासिक कोटा दिया जाता है;

(ख) क्या इसके परिणामस्वरूप सरकार का परिवहन पर बहुत अधिक खर्चा होता है; और

(ग) क्या देश में हुई बहुत अच्छी गेहूं की फसल तथा बहुत अधिक परिवहन व्यय को ध्यान में रखते हुये, सरकार का विचार आटा मिलों को आयातित गेहूँ सप्लाई करने के स्थान पर देसी गेहूँ सप्लाई करने का है ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) जी हां।

(ख) आटा मिलों को रेल तक निष्प्रभार गंतव्य स्थान तक आयातित गेहूँ सप्लाई की